है और इस पानी में हम कुछ लेना कम भी करते हैं जब कि पानी की कमी बहुत फरक्का के बेराज में आ जाती है, अन्यथा हमारी आवश्यकता के अनुरूप जो नहर बनाई गई है, उस नहर में हम अधिक से अधिक वहां से 40 हजार क्यूसिक पानी ले सकते है ।

SHRI G. G. SWELL : I am happy that Mr. Gujral has intervened before me. I read a report that he had been to Dhaka and he has reportedly said that if Bangladesh agrees to the inter-country river transportation between the North-East and Bangladesh, there would be more water for Bangladesh. On what basis he said that the Minister could clarify it.

I think after what happened in the Geneva Human Rights Commission, Bangladesh like the rest of the world would know that India cannot be pressurised against its interests and the best way to settle matters is to settle them amicably to mutual interest on the basis of give and take. But I am intrigued by a part of the statement of the Ministry because it seems that already Indo-Bangladesh Joint Committee had agreed to the enlargement of the Farakka. So long it was the Ganges, it was Farakka and less water to Bangladesh. Now you speak of the arrangement for sharing of the flow of the major rivers. What are those major rivers ? One of them could be the Bramhaputra. There has been some discussion about that. What are the other rivers ? I would like to know whether Bangladesh has agreed to this suggestion of sharing the flows of the major rivers.

The last point is this. We know of all kinds of elements in Bangladesh. I would like to know whether the countries or intelligence services which are hostile to us, who are trying to spoil relations with Bangladesh.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The hon. Member has rightly pointed out that other rivers are also involved if this augmentation matter is ultimately agreed to. The other rivers are the Tista and the Barak These are other two major rivers that would be involved in this thing. We have been keeping a very clear picture of the hydrology of the area, the topography of the area. I am sure our counterpart in Bangladesh also would know about it because these are the things which cannot be changed by any human endeavour. Therefore, ultimately the augmentation business will come through and it only requires patience and accommodation which so far Bangladesh Government has shown to us and we hope that this will continue and enable us to reach an agreement

MR. CHAIRMAN : Q. No. 282.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : From water to milk.

MR. CHAIRMAN : Instead of water, milk.

Purchase of Milk From Private Suppliers By Delhi Milk Scheme

*282. SHRI SOM PAL : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Millk Scheme (DMS) has been purchasing milk from private suppliers instead of cooperatives for some time ;

(b) if so, what were the considerations for doing so and at what level the decision was taken and when it was taken ;

(c) whether there have been complaints of inferior quality milk being supplied by the private suppliers ;

(d) whether the DMS have been incurring heavy losses, if so, what are the details thereof for the past three years ;

(e) what are the prices paid and charged for milk currently and whether these have any relation to the prices received by the producers ; and

(f) what is being done to improve the functioning of the DMS and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) to (f) A statement has been placed on the table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The Delhi Milk Scheme is procuring milk from State Dairy Federations ; Local Cooperative Societies as well as from private suppliers. The Delhi Milk Scheme had to resort to purchase of milk from private suppliers as during 1991, the State Dairy Federations withheld supply of milk with a view to force a hike in their sale price of milk. This led to disruption of milk supply by DMS to the consumers and caused great inconvenience to the citizens of Delhi. Therefore. a policy decision was taken to widen the source of procurement and it was decided in 1991 to procure the requirements of milk by inviting open tenders for the year 1992 & 1993. The same policy has been continued for 1994.

(c) The Delhi Milk Scheme accepts the raw milk only after it passes the prescribed quality standard tests.

(d) The estimated losses incurred by DMS in last five years are as under :—

(in Rs. Crores)

Years	Losses
1988-89	18.88
1989-90	16.51
1990-91	15.38
1991-92	35.12
1992-93	33 18

(e) A Statement—I is annexed (*See* below). The pricees paid to the Federations and Cooperative Dairy Societies are reasonable and competitive.

(f) The Delhi Scheme is modernising its plant and machinery to cut dov maintenance losses. The distribution network is also being strengthened and distribution routes have been rationalised so as to reduce transportation cost and distribute maximum milk per van per kilometer. Substantial economies have been obtained in the consumption of diesel oil, lubricant, electricity, water etc. besides reduction in milk handling losses.

Statement I

Purchased Price of Mixed Milk during the Year 1992 to 1994 of different sources

(Figures in Rs./Kg.)

Sl. No.	Name of source	1992			1993			1994		
		Flush	Transitory	Lean	Flush	Transitory	Lean	Flush	Transitory	Lean
		Jan., Feb., Nov. & Dec.	Mar., Apr., Sept. & Oct.	May, Jun., July & Aug.	Jan., Feb., Nov., & Dec.	Mar., Apr., Sept. & Oct.	May, Jun., July & Aug.	Jan., Feb., Nov. & Dec.	Mar., Apr., Sept. & Oct.	May, Jun., July & Aug.
1	Contractors	7.10	8.10	8.75	7.39	8.39	8.89	6.90	7.90	8.40
2	State Dairy Federations	8.06	8.67	9.27	7.56	8.17	8.77	7.20	7.76	8.36
3	Cooperative Diary Societies	7.10	8.10	8.75	6.75	7.95	8.35	6.62	7.82	8.22

Sale Price of DMS Different Types of Milk as on Date

Type of Milk	Sale Price (in Rs./Per litre)
Toned Milk	7.00
Swasth Milk (Double Toned Milk)	6.00

श्री सोमपाल : माननीय सभापति जी, मैंने दिल्ली दुग्ध योजना के संबंध में विस्तृत सवाल पूछा था और प्रयास यह किया था कि मैं सारे बिन्दु लिखित में पूछ लूं ताकि मंत्री जी को मौलिक प्रश्न पूछने की असुविधा कम दूं। पर, उन्होंने मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में सारे बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाला है। जो कारण उन्होंने सहकारी समितियों के बजाय निजी ठेकेदारों से दूध लेने के दिए हैं, वह न केवल अपर्याप्त हैं बल्कि अस्पष्ट भी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और विशेषकर डा० जाखड़ का सहकारिता आंदोलन के प्रति अनुराग सर्वविदित है। इस नीतिगत प्रश्न के ऊपर दिल्ली दुग्ध योजना के संबंध में इस निति का प्रतिवर्तन करने, इसको उल्टा करने, के मुख्य कारण क्या हैं ? जो दूध सप्लाई करने वाले निजी ठेकेदार हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं और वे कितना दूध सप्लाई करते हैं और सहकारी समितियां कितना दूध सप्लाई करती है ? शुरु में 96 पैसे कम के ऊपर निजी ठेकेदारों को इसने इंटरोड्यूस किया गया और स्थिति अब यह है कि वे सहकारी समितियों से 54 पैसा महंगा दूध दे रहे हैं। तो यह किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं ?

MR. CHAIRMAN : You have asked all the questions. Please sit down.

श्री सोमपाल : सर, मैंने सारा पूछ लिया है। My supplementary was not too long.

MR. CHAIRMAN : Then, allow the Minister to reply.

SHRI SOM PAL : I have tried to be very brief.

MR. CHAIRMAN : In fact you have asked many things.

SHRI SOM PAL : I must say, I hafe been very brief.

MR. CHAIRMAN : I am very happy.

श्री अरविन्द नेताम : सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, करीब-करीब प्रयास यह किया गया है कि उसका विस्तृत उत्तर दिया जाए और ऐसा भी किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को जितना प्रोत्साहन देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है, यह बात सही नहीं है। परन्तु इसके पीछे भी कारण हैं कि 1991 से पहले पूरा दूध.... (व्यवधान)

श्री सोमपाल : भुगतान के विषय में मैंने नहीं कहा, मैंने कीमत के अंतर के बारे में कहा है। देखिए, सदन को गुमराह मत कीजिए। मैंने कीमत के अंतर के विषय में कहा है। इसी के ऊपर आप रहिए। मैंने कहा कि जो वह सस्ता देते थे और बाद में मंहगा दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया गया और यह नीतिगत निर्णय क्यों बदला गया ? यह आपने उत्तर में नहीं बताया है।

श्री अरविन्द नेताम : मैं बता रहा हूं। 1991 से पहले पूरा दूध सहकारी क्षेत्र से आता था। पर, 1991 में बहुत सी परेशानी हुई। सहकारी क्षेत्र का, फेडरेशन का जो कमिटमेंट था, वह कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ और कीमतें बढ़ाने का दबाव मंत्रालय पर आया। इस वजह से भी यह सोचा गया कि कब प्राईवेट सैक्टर को

भी इसमें इंवोल्वड किया जाए, ताकि दिल्ली में दूध की सप्लाई बराबर बनी रहे। ऐसा सोचकर के यह नीतिगत फैसला किया गया कि सहकारी क्षेत्र के साथ-साथ प्राईवेट सैक्टर को भी इसमें इंवोल्वड किया जाए।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्य ने रेट के बारे में कही, तो वैसे भी अगर देखेंगे कि इस साल का जो रेट है—प्राईवेट कांट्रेक्टर को 7 रुपए 50 पैसे का है जो फेडरेशन को 7 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सहकारिता क्षेत्र को ज्यादा ही दिया है प्राईवेट सैक्टर के मुकाबले में। सभापति महोदय, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। प्राइवेट सैक्टर का टैंडर के माध्यम से होता है और फैडरेशन व सोसाइटी का नेगोशिएशन से होता है। तो इस प्रकार से इसमें किसी को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके आधार पर किया जाता है। जो और बातें आई हैं, उनको मैंने मूल प्रश्न में स्पष्ट किया है।

MR. CHAIRMAN : Second supplementary.

SHRI SOM PAL : Sir, the senior Minister is replying.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : He is supplementing, Sir.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (Shri Balram Jakhar) : Yes, I am supplementing.

सभापति महोदय, माननीय सदस्य सोमपाल जी ने जो बात पूछी, मैं भी यही चाहता था, हमेशा से विभाग में यह था कि जितना प्रोत्साहन दिया जा सके सहकारिता को, वह दिया जाए लेकिन यहां की जो सहकारिता की हमारी सोसायटीज हैं, उन्होंने और दूसरों ने जिस तरीके से डी०एम०एस० को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उससे हमें यह सोचना पड़ा कि दिल्ली के निवासियों के लिए दूध की सप्लाई का प्रबंध पूरा किया जाए और उस हिसाब से किया जाए। जो भी कुछ किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया। यह भी है कि यहां की जो सोसायटीज थी, उनका भी निरीक्षण करवाया गया और उस में से कई बोगस पाई गई। मैंने अब भी उनको कहा है और अब भी मेरा यह सिद्धांत है कि जो सहकारी समिति ठीक ढंग से काम करेगी, हम उसको पूरा प्रोत्साहन देंगे और यही हमारा निश्चय है लेकिन इस तरीके से नाम सोसायटीज का हो, काम करने वाला कोई हो, तो यह बात गलत हो जाती है और अब भी मैंने यही कहा है और 50 प्रतिशत हम दे रहे हैं और 50 प्रतिशत के हिसाब से इतना बड़ा घाटा हुआ है। इसमें ये दिया गया है। आप देखेंगे कि कितना घाटा इस साल हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि इस साल का घाटा 15 करोड़ रुपए पर आ गया है, 32 करोड़ रुपए से। तो यह सारा इसलिए किया गया है और यह भी देखा गया है कि कोई ऐसा काम न हो जिससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो और उसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं और जिस तरह प्रावधान किया गया है टेंडर्स का, उसमें कोई हेरा-फेरी नहीं कर सकता है। कतई उसको मौका नहीं दिया गया कि कोई आदमी इसका नाजायज फायदा उठा सके और जो दोषी होगा उसको सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर इसका जो घाटा है वह 119 करोड़ रुपए हो चुका है, क्युमुलेटव लॉस और वर्तमान वर्ष के बजट में 1994-95 में इस घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए केवल आपने 5 माह के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। तो उसके बाद क्या आप दिल्ली दुग्ध योजना को बंद करने जा रहे हैं या उसका निजीकरण करने जा रहे हैं या किसी और प्राधिकरण या सरकार को इसको हैंडओवर करने जा रहे हैं ? यह मेरे प्रश्न का "क" भाग है।

मेरे प्रश्न का "ख" भाग यह है कि कुछ समय पूर्व यह शिकायत मिली थी कि ये निजी सप्लॉइर दूध में कास्टिक सोडा और यूरिया मिलाकर, उसकी डैंसिटी बढ़ाने के लिए, दिल्ली दुग्ध योजना को सप्लाई कर रहे है और ये मामला उपभोक्ता न्यायालय तक भी पहुंचा। उन लोगों के क्या नाम हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और क्या वह आज भी उन सप्लाइरों में शामिल है ? सहकारिता के एकाधिकार को रोकने के लिए आपके पास मॉडल कोआपरेटिव लॉ का प्रारूप पड़ा हुआ है, उसे आप क्यों नहीं क्लियर करते जिसके कारण यह एकाधिकार होता है और ये बोगस सोसायटीज बनती है। आप उसे क्यों रखे बैठे हैं इतने दिनों से मंत्रालय में ?

श्री बलराम जाखड़ : प्रावधान तो इस हिसाब से किया गया है, जैसा मैंने पहले उत्तर दिया था, आपको समझ जाना चाहिए था सोमपाल जी कि इस साल का जो घाटा है, मैं उसको खत्म करने पर तुला हुआ हूं और अगले साल मेरे ख्याल में जो प्रावधान किया गया है, उसके नीचे घाटा रहेगा और वह एक-दो करोड़ रुपए के बीच में रहेगा। वैसे तो मेरे डिपार्टमेंट ने आंका है तकरीबन 5 करोड़ लेकिन वह कंजरवेटिव इस्तेमाल नहीं है, पूरा लिबरल उन्होंने लगाया है और अगले साल हम घाटा कम कर देंगे। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है इसका क्या करेंगे, तो आपके कोआपरेटिव लॉ का मामला तकरीबन पूरा हो चुका है। मैं उसको लाकर कैबिनेट से एप्रूव कराकर आपके सामने रखूंगा कि आप उसको पास कर दें और हम उस को लागू कर दें ताकि जो कोआपरेटिव सोसायटीज बेबुनियादी होती हैं, ये जन्म ही न लें जिससे न बांस हो और न बांसुरी बजे।

श्री सोमपाल : वह जो यूरिया का जहर मिलाने का सवाल है.. **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मैं बता रहा हूं। उसके लिए ऐसा है कि हमने ऐसी तरकीब लगाए रखी है इसमें कि जितना भी दूध होता है, उसका पहले टेस्ट होता है और टेस्ट की सारी वजहात होती हैं। हरेक आदमी जो करता है उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है और उस पर पैनल्टी लगाई जाती है एकदम से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने सारा का सारा काम जो किया है, इतना डेरा सारा काम है, इतने रिजेक्शंस हुए हैं, इतने जुर्माने किए गए हैं कि कोई गलत काम हो नहीं सकता कि वह गलत काम करके हमें सप्लाई कर दें। हम बिल्कुल लेते नहीं हैं। फैट के हिसाब से और एस०एन०एफ० के हिसाब से उसकी पूरी प्रक्रिया की जाती है टेस्टिंग की, उसके बाद वह लिया जाता है।

श्री सोम पाल : मैंने जो पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया माननीय मंत्री जी ने। मैंने यह पूछा है कि जिनके खिलाफ ये शिकायत हुई थी, उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही आपने की है ? केवल जुर्माने से काम नहीं चलता। यह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ का सवाल है ... **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : हमने यह कहा है आपको कि हम दाखिल ही नहीं होने देते जब तक कि टेस्ट नहीं हो जाता और हरेक को जुर्माना किया जाता है, सप्लाई के हिसाब से जुर्माना किया जाता है ... **(व्यवधान)**

श्री सोमपाल : उनके नाम क्यों नहीं बताना चाहते ?

श्री बलराम जाखड़ : ... **(व्यवधान)**

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, नाम नहीं बताना चाहते उन लोगों के। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ... **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : अगर किसी ने किया है तो किसी को बचाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता .. **(व्यवधान)**

श्री अरविंद नेताम : सभापति महोदय, करीब 8 प्राईवेट फर्म्स हैं जो दूध सप्लाई करती हैं जनवरी से लेकर दिसम्बर, 1993 तक की लिस्ट मेरे पास है । कहिए तो मैं पूरे 8 नाम बता दूं ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You don't have to read the whole list. I do not give time to read the whole list.

SHRI ARVIND NETAM : I can place it on the Table of the House, Sir.

(*Interruptions*)

SHRI SOM PAL : They are still continuing to supply, Sir, the same people, who have defaulted.

MR. CHAIRMAN : The Minister has said he has stopped.

SHRI SOM PAL : This is a very important information.

(*Interruptions*)

SHRI BALRAM JAKHAR : Mr. Chairman. Sir, there is no question of favouring anybody whatsoever. We cannot play with the life of the people. It is impossible.

SHRI SOM PAL : Sir, this is a very ambiguous reply. This is totally ambiguous. I want specific information about the people who have defaulted, what action has been taken against them, and whether they still continue to supply.

(*Interruptions*)

SHRI BALRAM JAKHAR : We don't accept the milk which is adulterated or sour. ... (*Interruptions*) ... We don't accept it. We don't accept it.

(*Interruptions*)

श्री० विजय कुमार मल्होत्रा : वह सप्लाई कर रहे हैं या नहीं, यह बताइए ... (व्यवधान)

श्री सोमपाल : आप इंस्ट्रक्ट करिए सर, मंत्री जी को ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. He has answered the question and he will give you further information.

SHRI SOM PAL : Sir, I seek your protection. You instruct him. This is a very serious matter.

MR. CHAIRMAN : He placed the information on the Table of the House.

(*Interruptions*)

SHRI SOM PAL : Are they still supplying it or not ?

SHRI BALRAM JAKHAR : I do not know ... (*Interruptions*) ... Sir, we have already clarified that the milk which is not up to the standard is not acceped.

SHRI SOM PAL : I am asking about the action taken against the defaulters and this is part of my original question. ... (*Interruptions*) ... My point was given in writing ... (*Interruptions*) ...

SHRI BALRAM JAKHAR : We punish them and we don't accept ... (*Interruptions*) ...

SHRI SOM PAL : Sir, he is again evading ... (*Interruptions*) ... Mr. Chairman. I take strong exception to concealing the information whether action was taken against the defaulters ... (*Interruptions*) ... This is very important and material and this is part of my original question.

SHRI BALRAM JAKHAR : I don't accept it.

SHRI SOM PAL : It is not a question of your accepting. This is Parliament. How can you say 'I don't accept your question' ? Why did you admit my question ? You have to reply. ... (*Interruptions*) ...

SHRI BALRAM JAKHAR : We have done it. There is no question of ... (*Interruptions*) ....

SHRI SOM PAL : Sir, this is an important matter. How can he say he does not accept a question which has been admitted ?

MR. CHAIRMAN : Mr. Som Pal. please sit down. ... (*Interruptions*) ... I must give an end to it, Mr. V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the hon. Minister was telling us that he revised the policy when the cooperatives refused to supply the milk. ... (*Interruptions*) ... Some of them are bogus and some of them corner more price. The Minister has given a table showing the purchase of milk from the private sector and the cooperatives. I will give one example. During the lean period from the contractor they get milk at Rs. 8.89 and from the cooperatives they get it at only Rs. 8.35. They pay more price to the contractors and less price to the cooperatives. That being the case, what prompted the hon. Minister or the D.M.S. to purchase milk at a higher price from the private suppliers, ignoring the cooperative which are supply milk at a lesser price. The D.M.S. is selling the milk at subsidised rate to the consumers. In the open market it is sold at Rs. 10. They are buying at Rs. 7. A lot of black marketing is going on. This is a very serious matter. These people purchase it in bulk quantities from the DMS counter sell it to the consumers at Rs. 10 per kilogram. I would like to know what action he is going take to counter this and to ensure regular distribution of milk to the real consumers in Delhi.

SHRI BALRAM JAKHAR : Sir, we have to check the black marketing and those people who are thriving (*Interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANASAMY : This is going on. (*Interruptions*) ...

SHRI BALRAM JAKHAR : This is a question which has to be dectded by us. We have to check it to ensure supply of milk. (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN : Please. Let us hear him. There is no point in background noise.

SHRI BALRAM JAKHAR : One of the causes for loss to the DMS is that we supply it at a lower price than we pay for procurement, the production, processing and other things. The second thing is that we have continuing contracts with co-operative federation and co-operatives. When they try to put pressure on us and try to blackmail us by stopping supply of milk, we have to incur loss to make substitute milk. That was the reason. No it is all right. We are paying more to the federation than to the private owners.

SHRI K. R. MALKANI : Mr. Chairman, does the hon. Minister think that it is enough to impose a fine of Rs. 5 on people who mix chemical fertilizer with milk ? Would he consider debarring such people from further supplying milk to the DMS ?

SHRI BALRAM JAKHAR : There is no question of mixing. It is a question of milk getting soured or something like that. When it falls below the standard of SNF and fat we reject it and charge penalty for that (*Interruptions*) ... You have to get supply from other sources. You have to supply milk. When you supply certain things. ... (*Interruptions*) ... It may happen in a centre. It is there all over the country, not here alone. (*Interruptions*) ... When it gets soured or becomes worse or becomes acidic or something like that we don't accept that milk. That is also a penalty. That is also a punishment. (*Interruptions*) ...

SHRI K. R. MALKANI : Mixing chemical fertilizer is entirely different and that is the allegation of Mr. Som Pal.

MR. CHAIRMAN : The Minister said that he was not accepting such allegations. Shrimati Satya Bahin.

श्रीमति सत्या बहिन : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे समय दिया । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है या शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली दुग्ध योजना के

कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों ने भी अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने नौकरों के नाम दूध की सप्लाई करने वालों में लिखवा रखे हैं और टैंकरों को ले रखा है? अगर इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं तो क्या उनकी जांच की गई है ? दूसरा इसी से संबंधित सवाल यह है कि आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ जिन पर अनियमितताओं की शिकायतें हैं, मिलावट की शिकायतें हैं क्या उनके विरुद्ध कोई जांच की गई है और अगर की गई है तो क्या उनमें कोई दोषी पाया गया है ? क्या यह भी सही है कि ऐसे लोग जिन पर जांच चल रही है और दोषी भी पाए गए हैं उनके द्वारा भी दूध की आपूर्ति की जा रही है ? इन दोनों का सवाल मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं ।

श्री बलराम जाखड़ : अगर बेईमानी नहीं है तो झगड़ा किस बात का है । कोशिश की जाती है कि उनको चैक भी किया जाए, पकड़ा भी जाए और सुपरविजियन भी किया जाए । We are trying to do our best. हर रिजेक्शन पर पांच हजार से सात हजार पैनल्टी भी लगती है।

MR. CHAIRMAN : Shri Surjewala.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : 6 महीने की सजा; एक साल की सजा की बात करते हैं लेकिन दिल्ली मिल्क स्कीम के दूध को न कोई चैक कर सकता है, न कोई टेस्ट कर सकता है । कोई सजा नहीं हो सकती है . . . (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN : I have called another Member already.

SHRI S. S. SURJEWALA : Mr. Chairman, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that during the month of summer the prices of milk are artificially controlled by putting a ban on the making of milk products like *khoya, paneer*, etc., for the benefit of other consumers. I would like to know why this restriction has been put on the produce of the milk producers and the farmers. Why have they been deprived of this market benefit when liberalisation is taking place in the country and the industrialists and other manufacturers are allowed to take the benefit of the market conditions ? Why have the farmers or the milk producers been deprived of the benefit of the liberalisation policy of the Government ? Will the Government consider nit putting any kind of ban on milk products ?

SHRI BALRAM JAKHAR : It is a very good question and the answer must also be good. I think the hon. Member wanted to know why milk products were not being supplied to Delhi during the months of summer. I will try to see that this does not happen again.

Occupation of Government Land on Lease by Delhi Golf Club

*283. SHRI SANJAY DALMIA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Golf Club is occupying Government land on lease ;

(b) whether the lease has recently been renewed and if so, at what rate, terms and conditions ;

(c) what is the existing market rent for similar size of land on lease and whether the same is being charged from Delhi Golf Club ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. Delhi Golf Club is accupying Government land measuring 179 acres on Dr. Zakir Hussain Marg which was leased out by the Government on temporary lease basis to them.